



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2014/कार्तिक 23, 1936

No. 596]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2014/KARTIKA 23, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(निःशक्तता कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2014

सा.का.नि. 809(अ).—राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 या jsda-msje@nic.in को भेजे जा सकेंगे;

आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"4. अध्यक्ष के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव—

(1) न्यास के अध्यक्ष की अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :--

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या शिक्षाशास्त्र या मनोविज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री ; या

निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी अर्हता के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विद्याशाखा में स्नातकोत्तर डिग्री :--

(क) एक या अधिक निःशक्तताओं, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता में शिक्षा स्नातकोत्तर ; या

(ख) एक या अधिक निःशक्तताओं, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता में शिक्षा स्नातक ; या

(ग) एक या अधिक निःशक्तताओं, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता में डिप्लोमा ;

(ii) प्रख्यात वृत्तिक जरनलों में अनुसंधान पत्र के प्रकाशन को अतिरिक्त अर्हता के रूप में माना जाएगा ।

(2) अध्यक्ष के पास निम्नलिखित अनुभव होगा, अर्थात् :--

(क) निःशक्तता सेक्टर में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता में होना चाहिए ; और

(ख) किसी ऐसे गैर सरकारी संगठन के, जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष से सेवा कर रहा है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष या प्रधान या महासचिव के रूप में तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ।

(3) अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बासठ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

4क. अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया—

अध्यक्ष, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सुसंगत क्षेत्र में का ज्येष्ठ प्रख्यात शिक्षाविद अध्यक्ष ;

(ii) सचिव, निःशक्तता कार्य विभाग सदस्य ;

(iii) मुख्य आयुक्त, निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति सदस्य ;

(iv) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रबंध निदेशकों या अध्यक्षों में से दो प्रख्यात विशेषज्ञ सदस्य ।

४ख. अध्यक्ष का वेतन-

अध्यक्ष का वेतन, भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन के समतुल्य होगा और यथा अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता होगा :

परंतु जहां अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या अर्द्ध सरकारी निकाय या लोक उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या अन्य स्वशासी या कानूनी निकाय का कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, वहां उसे देय वेतन और उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत सुविधाओं का पेंशन मूल्य भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन से अधिक नहीं होगा ।"

【फा. सं. 1-4/2012-डी.डी.-IV(वोल्य. 3)】

मुकेश जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 639(अ), तारीख 26 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना तारीख 24 दिसंबर, 2010 संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Disability Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2014

G.S.R. 809(E).—The following draft of certain rules further to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, which the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 read with clause (b) of sub-section (2) of Section 34 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Joint Secretary, Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110115 or by email at jsda-msje@nic.in;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft Rules before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These Rules may be called National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2014.
 (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, for Rule 4, the following shall be substituted, namely:-

"4. Educational qualification and experience required for Chairperson.-

(1) The Chairperson of the Trust shall have the following qualifications, namely:-

(i) Master's Degree in Sociology or Education or Psychology or Social Work from a recognised University; or Post Graduate degree in any other discipline from a recognised University with any of the following qualifications;

(a) Master in Education in one or more of the disabilities, namely, autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities; or

(b) Bachelor in Education in one or more of the disabilities, namely, autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities; or

(c) Diploma in one or more of the disabilities, namely, autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities;

(ii) Publication of research papers in reputed professional journals shall be considered as additional qualification.

(2) The Chairperson shall have the following experience, namely:-

(a) minimum fifteen years of experience in the disability sector of which not less than ten years in autism/cerebral palsy/mental retardation/multiple disabilities; and

(b) administrative experience of not less than three years as Chief Executive Officer or Chairperson or President or General Secretary of any Non Governmental Organisation which has been serving at least for ten years in the areas of autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities;

(3) The Chairperson shall not be older than sixty-two years as on the closing date of receipt of applications by the Central Government.

4A. Procedure for selection of Chairperson.-

The Chairperson shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a search-cum-selection committee consisting of the following, namely:-

(i) A senior distinguished academician in the relevant field to be nominated by the Minister Social Justice and Empowerment.....Chairman;

(ii) Secretary, Department of Disability Affairs.....Member;

(iii) Chief Commissioner for Persons with Disabilities.....Member;

(iv) Two experts of eminence amongst the Managing Directors or Chairperson of Non Governmental Organisations working in the field of Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, Multiple DisabilitiesMembers.

4B. Salary of Chairperson.-

The salary of the Chairperson shall be equivalent to the basic pay of the Secretary to the Government of India and dearness allowance and city compensatory allowance as admissible:

Provided that where the Chairperson is a retired person from the Central Government or a State Government or Union territory Administration or semi-Government body or public sector undertaking or a recognised research institution or any other autonomous or statutory body, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminable benefits or both received by him shall not exceed the basic pay of Secretary to the Government of India."

[F. No. 1-4/2012 - DD-IV (Vol.-III)]

MUKESH JAIN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 639(E) dated the 26th July, 2000 and was last amended *vide* notification dated 24th December, 2010.